मजदूरों का अपना कोई देश नहीं होता ।

दुनियां के मजदूरो, एक हो ।

फरीदाबाद मजदूर समाचार

मजदूरों की मुक्ति खुद मजदूरों का काम है ।

दुनियां को बदलने के लिए मजदूरों को खुद को बदलना होगा ।

RN 42233 पोस्टल रजिस्ट्रेशन L/HR/FBD/73

नई सीरीज नम्बर 44 | फरवरी 1992 | 50 पैसे

झलानी टूल्स

सैकन्ड प्लान्ट के मजदूर दस जनवरी को हक्के-बक्के रह गये। कई मजदूरों की दिसम्बर 91 की तनखा में से आठ-आठ सौ, नौ-नौ सौ रूपये मैनेजमेंट ने काट लिये थे। वेतन में यह कटौती पे-स्लिप में भी दर्ज थी।

गेडोर उर्फ झलानी टूल्स की मैनेजमेंट और वहाँ के बिचौलिये फरीदाबाद में कुख्यात हैं। 1982-83 में काफी पापड़ बेलने के बाद भी छंटनी नहीं कर पाये पर 1984 में डेढ हजार मजदूरों को नौकरी से निकालने के लिये गेडोर मैनेजमेंट को बिचौलियों के जरिये मार-मार कर मजदूरों से जबरन इस्तीफे लिखवाने पड़े थे। छंटनी के बाद वहाँ बचे ढाई हजार मजदूरों में जब-तब कुछ हलचल होती रही है पर आमतौर पर मजदूर सहमे-से, डरे से रहते रहे हैं।

सैकन्ड प्लान्ट के डेढ सौ-क मजदूरों की तनखा में कटौतियां की गई थी। बात फैलने पर डर की जगह मजदूरों का गुस्सा भड़क उठा। मजदूरों के सामुहिक गुस्से को देख कर मैनेजमेंट व बिचौलियों में खुसर-पुसर हुई और वेतन से काटे गये पैसे मजदूरों को दे दिये गये।

मामला शान्त सा हो गया पर मजदूरों की चिन्ता बढ गई। कुछ मजदूरों ने बिचौलियों से तनखा में कटौती का कारण जानना चाहा तो उन्हें धमकियाँ दे कर चुप करने की कोशिश की गई। लेकिन इस मामले में मजदूर चुप नहीं हुये।

आपस में सलाह-मशविरा करके मजदूरों ने लिखित में मैनेजमेंट से तनखा में कटौती का कारण पूछने का तय किया। मैनेजमेंट ने मजदूरों के पत्र लेने से इनकार कर दिया। मैनेजमेंट के किसी पत्र को जब कोई मजदूर लेने से इनकार कर देता है तो इसे स्थाई आदेशों का उल्लंघन करार दे कर एक और आरोप उस मजदूर पर लगा दिया जाता है।

खैर, झलानी टूल्स के मजदूरों ने अपने पत्र यू० पी० सी० डाक से मैनेजमेंट को भेजे हैं। साथ ही, इन मजदूरों ने डी० यल० सी० को भी इस मामले में आवेदन दिये हैं

दरअसल सेकन्ड प्लान्ट के मजदूरों के वेतन में कटौती वाला यह घटनाक्रम सूई चुभा कर मजदूरों का रियेक्शन आँकने तथा उनमें डर पैदा करने के लिये मैनेजमेंट+बिचौलियों की एक हरकत थी। मैनेजमेंट+बिचौलिये अपने एक अजूबे फैसले समझौते को मजदूरों पर थोप रहे हैं।

उस अजूबे की एक झलक देखिये :— मजदूरों द्वारा आठ घन्टे काम करने को चार घन्टों का प्रोडक्शन माना जायेगा। मैटेरियल देने और बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की नहीं होगी। प्रत्येक मजदूर को किसी भी मशीन, किसी भी जॉब, किसी भी काम पर लगाया जा सकता है

साफ है कि मामला सैकन्ड प्लान्ट के कुछ मजदूरों का ही नहीं है बल्कि यह झलानी टूल्स के फरीदाबाद स्थित तीनों प्लान्टों के ढाई हजार मजदूरों को जकड़ने की बात है।

मैटेरियल नहीं था तो क्या हुआ, प्रोडक्शन तो कम हुआ — सेकन्ड प्लान्ट के डेढ सौ-क मजदूरों के वेतन में से आठ-आठ सौ, नौ-नौ सौ रुपये काटने के लिये मैनेजमेंट+बिचौलियों की यह है असल दलील। खुसर-पुसर कर बाद में काटे हुये पैसे लौटा देना मैनेजमेंट+बिचौलियों के एक और प्रयोग का पूरा होना है। बीस-पचास रुपये तीनों प्लान्टों के मजदूरों के वेतन से इस आधार पर पहले भी काटे गये है।

मामला झलानी टूल्स मजदूरों के लिये गम्भीर है। मजदूरों की सामुहिक ताकत ही मजदूरों के देख-भाल कर सकती है गेडोर-झलानी टूल्स के मजदूरों को याद करना चाहिये कि कैसे 1983 में मजदूरों की साँझी शक्ति ने बिचौलिया सरदार, फरीदाबाद सीटू के प्रेसीडेन्ट को धूल चटा दी थी। मजदूरों की साँझी ताकत ने तब गेडोर मैनेजमेंट के भी दाँत खट्टे कर दिये थे। यह तो मैनेजमेंट+बिचौलिये+सरकार के गठजोड़ की ताकत थी जिससे गेडोर के मजदूर अकेले तौर पर नही निपट पाये थे।

इस समय के बिचौलिया प्रमुख 1984 में सीटू प्रधान के लठैत मात्र थे। मजदूरों की सामुहिक शक्ति इनसे आसानी से निपट सकती है। मैनेजमेंट+बिचौलिये+सरकार के गठजोड़ से भी झलानी टूल्स के मजदूर अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों से तालमेल-एकता कायम करने की राह पर बढ कर निपट सकते हैं। हिम्मत और हौसले की जरूरत है। झलानी टूल्स के मजदूरों का सचेत संगठित संघर्ष ही उनके हितों की देख-भाल कर सकेगा।

ओसवाल-जैन ग्रुप

प्लाट नम्बर 48 इन्डस्ट्रीयल एरिया और प्लाट नम्बर 23 सैक्टर 25 में ओसवाल इंजिनियरिंग, ओसवाल इलैक्ट्रिकल्स, जैन डाईकास्टिंग, ओसवाल प्रैशर डाईकास्टिंग, जैना कास्ट आदि फैक्ट्रियाँ हैं। इन फैक्ट्रियों में परमानेन्ट से ज्यादा ठेकेदारों के मजदूर काम करते हैं। परमानेन्ट मजदूरों को दबाने के लिये इस समय मैनेजमेंट ने हमले किये हुये हैं और मजदूर अभी डटे हुये हैं।

इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित ओसवाल इंजिनियरिंग मैनेजमेंट ने 1993 तक 20 परसैन्ट बोनस देने का समझौता किया हुआ हैं। मैनेजमेंट अपनी बात से मुकर गई है और 90-91 का 8.38 परसैन्ट बोनस देना चाहती है। मजदूरों के विरोध को कुचलने के लिए मैनेजमेंट ने दिसम्बर की तनखा 13 जनवरी को देने का वादा किया और छुट्टी के दिन 12 जनवरी को तालाबन्दी कर दी। ओसबाल इंजिनियरिंग के मजदूर फैक्ट्री गेट पर धरने पर बैठे हैं।

इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित जैन डाइकास्टिंग और सैक्टर-25 स्थित ओसवाल प्रेशर डाईकास्टिंग व जैना कास्ट मैनेजमेंट ने दो साल तक 20 परसैन्ट बोनस देने का समझौता किया हुआ है। यहाँ भी अपनी बात से मुकर कर मैनेजमेंट 8.33 परसैन्ट बोनस देना चाहती है। दबाव डालने के लिये मैनेजमैंट ने सात मजदूरों का 24 जनवरी को गेट रोक दिया और उनसे हिसाब लेने को कहा। इस पर जैन डाईकास्टिंग के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। सैक्टर 25 स्थित ओसवाल प्रेशर-कास्टिंग व जैना कास्ट के मजदूर भी 24 जनवरी को ही हड़ताल में शामिल हो गये। हड़ताली मजदूर अपनी-अपनी फैक्ट्री के गेट पर धरने पर बैठे हैं।

ओसवाल इलैक्ट्रिकल्स अभी चल रही है।

फैक्ट्री गेटों पर धरने पर बैठने और सरकारी साहबों के पास भाग-दौड़ से मजदूरों की बात नहीं बनेगी। इसलिये हड़ताली मजदूरों तथा तालाबन्दी के शिकार मजदूरों को अपनी ताकत बढाने के कदमों पर विचार करना चाहिये। हर रोज जलूस निकालना ऐसा एक कदम है। एक दिन इन्डस्ट्रीयल एरिया के मजदूरों का जलूस 25 सैक्टर के मजदूरों के पास जाये तो दूसरे दिन सैक्टर 25 के मजदूरों का जलूस इन्डस्ट्रीयल एरिया मजदूरों के पास पहुँचे। पाँच-छह दिन तक

शेष पेज २ में

बाटानगर हड़ताल

12 दिसम्बर 91 को 7250 मजदूरों में से 6612 ने हड़ताल के पक्ष में मत दिया। 3 जनवरी से बाटानगर (बँगाल) में हड़ताल है। 11 फरवरी को इन हड़तालो मजदूरों के समर्थन में भारत भर में बाटा कम्पनी की शाखाओं में एक दिन की हड़ताल की घोषणा है।

1988 में बाटानगर में तालाबन्दी करके मैनेजमेंट ने एक शर्त यह भी मनवाई थी कि सितम्बर 89 की बजाय नया एग्रीमेंट अपैल 91 में होगा। 18 अप्रैल 91 को 73 डिमान्डों वाला माँग-पत्र मैनेजमेंट को दिया गया। इस पर मैनेजमेंट ने 12 पाइन्ट का अपना चारटर पेश कर दिया। बातचीत शुरू करने के लिये मैनेजमेंट द्वारा रखी गई कुछ शर्तें यह थी :— 1) 73 डिमान्डों में से सिर्फ 14 पर ही बातचीत होगी ; 2) उत्पादकता बढाने के लिये स्टैन्डर्ड प्रोडक्शन प्रति मिनट तय किया जाये; 3] कुछ विभागों में लागू वेतन को उत्पादकता से जोड़ने वाली स्कीम फैक्ट्री में बाकी जगह भी लागु की जाये।

बाटा मैनेजमेंट एक दीर्घकालीन समझौता चाहती है जिसमें प्रत्येक मजदूर पर वर्क लोड बढेगा। इतना ही नहीं, बिचौलियों को किसी प्रकार की आड़ दिये बिना मैनेजमेंट खुल्लम-खुल्ला अपनी शर्तें थोपना चाहती है। ऐसे में बातचीत के नाम पर ड्रामा होने जब आठ महीने हो गये तब मजदूरों का असन्तोष काफी बढ गया। तीन जनवरी से हड़ताल जहाँ मजदूरों के गुस्से की अभिव्यक्ति है वहीं बिचौलियों के हाथों में हड़ताल का नेतृत्व इसकी कमजोरी की पूर्व-घोषणा भी है।

संघर्ष का नेतृत्व मजदूर बिचौलियों के हाथों से अपने हाथों में ले कर ही मजदूरों की हवा निकालने/मजदूरों को दलदल में फँसाने की शतरंजी चालों की काट कर सकेंगे। मजदूरों की आम सभा

शेष पेज २ में

हमारे लक्ष्य हैं — 1. मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिये इसे समझने की कोशिशें करना और प्राप्त समझ को ज्यादा से ज्यादा मजदूरों तक पहुचाने के प्रयास करना। 2. पूंजीवाद को दफनाने के लिए जरूरी दुनियां के मजदूरों की एकता के लिये काम करना और इसके लिये आवश्यक विश्व कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के काम में हाथ बटाना। 3 भारत में मजदूरों का क्रान्तिकारी संगठन बनाने के लिये काम करना। 4. फरीदाबाद में मजदूर पक्ष को उभारने के लिये काम करना।

समझ, संगठन और संघर्ष की राह पर मजदूर आन्दोलन को आगे बढ़ाने के इच्छुक लोगों को ताल-मेल के लिये हमारा खुला निमन्त्रण है। बातचीत के लिये बेझिझक मिलें। टीका टिप्पणी का स्वागत है—सब पत्रों के उत्तर देने के हम प्रयास करेंगे।

संपर्क — मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, बाटा चौक के पास, एन. आई. टी. फरीदाबाद121001

इमरजैन्सी/युद्ध और मजदूर

पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट की वजह से कुछ समय से दुनिया-भर में उथल-पुथल काफी तेज हो गई है। रूस-पूर्वी यूरोप जैसी कमजोर पड़ गई पूंजी इकाइयों में तो धमाके हुये ही है, अमरीका जैसी शक्तिशाली पूंजी इकाई में भी पूंजीवादी उद्यमों के दिवालिया होने की रफ्तार तेज है। ऐसे में भारत जैसी कमजोर पूंजी इकाई में भी चौंकानेवाली घटनायें हुई हैं पर रूस आदि के विस्फोटों की तुलना में फीकी होने की वजह से इन पर खास आश्चर्य नहीं हुआ है। लेकिन मजदूरों के लिये गम्भीर हालात यहाँ दिन पर दिन अधिक गम्भीर हो रही है।

कुछ समय से "देश गम्भीर आर्थिक संकट में हैं" के पूंजीवादी शोर-शराबे में मजदूरों व अन्य मेहनतकशों पर नित नये हमले सरकार कर रही है। भाजपा-जद-सी पी आई-सी पी एम आदि विरोधी पूंजीवादी पार्टियाँ सरकार के इन हमलों का रस्मी विरोध कर रही हैं। मजदूरों की तरफ से भी अब तक इन पूंजीवादी हमलों का अलग-अलग विरोध ही हो रहा है।

मजदूरों के अलग-अलग विरोधों को दबाने के लिये भी पुलिस को गोलियाँ चलानी पड़ी हैं। बढ़ते असन्तोष के बारूद में कोई हड़ताल प्रदर्शन-रेल/रोड़ जाम चिनगारी का काम कर सकता है। पूंजीवादी विद्वान यह बखूबी जानते है। इस समय वाले पूंजीवादी व्यवस्था के गहरे संकट के झटके से डूब जाने से बचने के लिये भारत-रूस में संगठित पूंजी इकाई को अभी तो निकट भविष्य में तेजी से एक के बाद दूसरा बड़ा हमला करना होगा। ऐसे में मजदूरों के सम्भावित प्रतिरोध से पूंजीवादी सरगने चिन्तित हैं।

एक पूंजीवादी राय मौजूदा जनतन्त्र के ड्रामे को जारी रखते हुये मजदूरों पर हमले बढ़ाने की है। जोर पकड़ रही दूसरी पूंजीवादी राय के अनुसार जिस पैमाने और जिस तेजी से पूंजीवादी हमले आवश्यक हो गये हैं वे मौजूदा संसदीय ड्रामेबाजी के चलते नहीं किये जा सकते। ऐसे पूंजीवादी तत्व आर्थिक इमरजैन्सी जैसे कदमों की वकालत भी करते रहे हैं। और फिर यहाँ हिटलरी तरीकों को हर मर्ज की रामबाण दवा मानने वाले पूंजीवादी तत्व हैं जो कि कुछ समय मे काफी तेजी से पूंजीवादी राजनीति में ताकतवर बन रहे हैं।

आज यहाँ पूंजीवादी पक्ष में तेजी से हावी सोच यह बन रही है कि मजदूरों व अन्य मेहनतकशों पर बड़े हमले करने के लिये तत्काल सख्त कदम उठाने जरूरी है। लेकिन वर्तमान संसदीय सन्तुलन में सामान्य परिस्थितियों में आर्थिक इमरजैन्सी लागू करना काफी कम सम्भावना लिये है। ऐसे में मजदूरों पर बड़े हमलों के लिये यहाँ पूंजीवादी तत्वों द्वारा अन्य आड़ तलाश करना, अन्य बहाने ढूंढना स्वाभाविक बन गया है।

पूंजीवादी व्यवस्था के गहराते संकट से ही पूंजी की पाकिस्तानी इकाई भी लड़खड़ा रही है। ऐसे में कश्मीर में मजदूरों-मेहनतकशों के बढ़ते असन्तोष का पूंजी की भारतीय इकाई के खिलाफ बगावत का रूप धारण करना और इस्लाम के झन्डों को थामना पाकिस्तान में पूंजीवादी सरगनों को अपनी बीमारियों की रामबाण दवा नजर आ रहा है।

कुछ परिस्थितियाँ कश्मीर में एक सीमित युद्ध की तरफ दोनों देशों के पूंजीवादी सरगनों को धकेल रही हैं। लेकिन ऐसे युद्ध में इन पूंजीवादियों के लिये खतरे भी बहुत हैं। इसलिये इस समय भारत व पाकिस्तान के प्रधानमन्त्री लड़ाई शुरू करें या नहीं करें कि ऊहापोह में हैं। ऐसे माहौल में भारत में प्रमुख विरोधी पूंजीवादी पार्टी का पूंजीवादी युद्ध के लिये यात्रा निकालना, कश्मीर के मामले में भारत की पूंजीवादी फौज का लड़ाई के लिये तत्पर होना; दुनियाँ की तेजी से बदलती पूंजीवादी गुटबाजी में अमरीका-ब्रिटेन की सरकारों द्वारा पूंजी की भारतीय इकाई की पीठ थपथपाना और पूंजी की पाकिस्तानी इकाई को आँखें दिखाना- यह सब कुल मिला कर कश्मीर को मुद्दा बना कर उपमहाद्वीप में एक सीमित पूंजीवादी युद्ध की सम्भावना बढ़ा रहे है। वैसे वी पी सिंह सरकार के वक्त भी एक बार ऐसा युद्ध शुरू होने की कगार पर था।

अतः पूंजीवादी जनतन्त्र के ड्रामे को जारी रखते हुये मजदूरों पर पूंजीवादी हमले तेज करना अथवा आर्थिक इमरजैन्सी लगा कर मजदूरों पर पूंजीवादी हमले तेज करना अथवा युद्ध के साथ इमरजैन्सी लगा कर मजदूरों पर पूंजीवादी हमले तेज करना ... इनमें से जो भी तरीका अमल में आये, आने वाले दिनों में भारत में और पाकिस्तान में मजदूरों पर पूंजीवादी हमले बढ़ेंगे। यह वर्तमान वस्तुगत परिस्थिति का लाजमी नतीजा है।

ऐसे में भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों में मजदूरों के लिये पहली जरूरत तो यह बनती है कि वे इमरजैन्सी अथवा युद्ध की आड़ में अपने पर होने वाले पूंजीवादी हमलों की हकीकत को समझें। पूंजीवादी युद्ध की स्थिति में देशभक्ति का ढोल कुछ ज्यादा ही पीटा जायेगा। देशभक्ति की अफीम के नशे में मदहोश हो कर खून-खराबे में शरीक होने से बचने के लिये जरूरी है कि पूंजीवादी युद्ध की हकीकत को मजदूर पहचानें। भारत-पाकिस्तान युद्ध असल में भारत के पूंजीवादियों और पाकिस्तान के पूंजीवादियों के बीच युद्ध होता है। कई बार ऐसा युद्ध दो देशों में मजदूरों को कुछ और निचोड़ने के लिये पूंजीवादियों की मिली-कुश्ती भी होता हैं।

दरअसल भारत में एक तरफ झुग्गी-झोंपड़ी-गन्दी बस्तियों में बदहाल लोग हैं तो दूसरी तरफ बड़ी बड़ी कोठियों, फाइव स्टार होटलों में मटरगश्ती करते भद्रजन हैं। यही हाल पाकिस्तान में हैं। इस हकीकत के मद्देनजर पूंजीवादी युद्ध की स्थिति में भारत व पाकिस्तान के मजदूरों को एक तरफ तो अपने ऊपर युद्ध की आड़ में बढ़ाये जाने वाले पूंजीवादी हमलों का विरोध करना चाहिये और दूसरी तरफ भारत व पाकिस्तान के मजदूरों को दुख-दर्द की जननी पूंजीवादी व्यवस्था को दफनाने के लिये मजदूर एकता की राह पर कदम बढ़ाने चाहियें।

प्याली में तालाबन्दी

पाँच सौ मजदूरों की छँटनी की तैयारी

11 जनवरी को फैक्ट्री में हंगामे के बाद इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित हितकारी पोट्रीज मैनेजमेन्ट ने तालाबन्दी कर दी।

घटना की जड़ में मैनेजमेंट की छँटनी स्कीम हैं। यह छँटनी फैक्ट्री में हो रहे आटोमेशन की उपज हैं। जर्मनी से मँगाई चार आटोमेटिक मशीनों से मेकिंग डिपार्ट में प्रोडक्शन शुरू भी हो गया है। मैनेजमेंट की आटोमेशन स्कीम की यह शुरूआत भर है। इस प्रकार पांच-छह सौ मजदूरों को नौकरी से निकालना मैनेजमेंट की कार्य सूची पर है।

प्याली में मजदूर पक्ष के उभरने के लिये जरूरी था कि फैक्ट्री के दम घोंटू माहौल और कम वेतन से परेशान मजदूर अपने पैरों पर खड़े होते। लेकिन मजदूरों की संगठित होने की कोशिश मार्च 91 में चौटाला की लूट मार संगठन की दलदल में फँस गई। जून 91 में संसदीय नाटकबाजी में देवीलाल-चौटाला के पिटने के बाद एल एम एस की धौंस पट्टी ना के बराबर रह गई। ऐसे में हितकारी पोट्रीज मैनेजमेंट ने चुपचाप अपनी आटोमेशन स्कीम पर अमल शुरू किया। सितम्बर 91 तक बिना किसी विरोध के चार आटोमेटिक मशीनें चालू हो गई। तब मैनेजमेंट ने एल एम एस के साथ अक्टूबर 91 में बिना किसी दबाव के माहौल में अपने मन माफिक एग्रीमेंट किया।

प्याली फैक्ट्री में संगठित मजदूर पक्ष के अभाव में मैनेजमेंट की आटोमेशन और उससे जुड़ी छँटनी की स्कीम हितकारी मजदूरों के बीच नंगी नहीं की जा सकी। नतीजा यह हुआ कि मजदूर पक्ष से मैनेजमेंट का विरोध नहीं हुआ। हाँ, एक लम्पट ग्रुप की जगह दूसरे लम्पट ग्रुप को उभार कर अपनी स्कीम लागू करने की मैनेजमेंट की तिकड़मों ने लम्पट बाजी के एक सिलसिले को जन्म दिया। मैनेजमेंट को मात देने की एक ग्रुप की हरकत एल एम एस का झन्डा छोड़ कर तिरंगे मगरमच्छ को दूसरे ग्रुप से पहले ले आई—मजदूर पक्ष के लिहाज से यह तवे से चूल्हे में कूदने वाली बात हुई।

मार-पीट, तालाबन्दी, गिरफ्तारियाँ, बिखराव: कुल मिला कर माहौल प्याली फैक्ट्री में ऐसा बन गया है कि मैनेजमेंट हावी हो गई है।

ऐसे माहौल को बदलने के लिये क्या करें? हमारे विचार से कुछ कदम जो प्याली फैक्ट्री मजदूरों को फौरन उठाने चाहियें वे हैं—1. साइड मीटिंगों का एक सिलसिला शुरू करके बिखराव की जगह एकबद्ध होने की कोशिश करना। 2. साइड मीटिंगों में पूरे घटनाक्रम पर विचार करके मजदूरों की आम सभा के कन्ट्रोल में हर रोज जलूस जैसे वे कदम उठाना जो कि मैनेजमेंट+सरकार वाले गठजोड़ के खिलाफ मजदूर पक्ष की ताकत बढ़ायेंगे।

हरे-तिरंगे-काले-पीले झन्डे थामे बिचौलियों और उनकी जयजयकार करते लम्पटों की जकड़ से स्वयं को छुड़ा कर ही प्याली के मजदूर अपने हितों की देख-भाल कर सकेंगे।

मामला हल्का-फुल्का नहीं है कि सरकारी खागड़ों के पास भाग-दौड़ अथवा पूंजीवादी कानूनों की दाँव-पेच से हल हो जायेगा। प्याली के पाँच सौ मजदूरों की नौकरी दाँव पर लगी है। हितकारी पोट्रीज के मजदूरों से विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

लगातार इस तरह के जलूस निकालने के बाद यह मजदूर इकट्ठे हो कर डी० सी० अथवा डी एल सी आफिस तक जलूस निकालें। उस जलूस में मजदूर अपने परिवार के सदस्यों तथा अन्य फैक्ट्रियों के सहयोगी मजदूरों को शामिल करने के प्रयास करें। जलूसों के इन सिलसिलों से मजदूर पक्ष की ताकत बढ़ेगी और हालात के मुताबिक मजदूर अन्य कदम भी उठा सकेंगे। ओसवाल इलैक्ट्रिकल्स के मजदूरों को आन्दोलन में शामिल करने के लिये संघर्षरत मजदूरों को विशेष प्रयास करने चाहियें ओसवाल इंजिनियरिंग, जैन डाईकास्टिंग, ओसवाल प्रशर डाईकास्टिंग, जैमा कास्ट के मजदूरों से विचार-विमर्श का हम स्वागत करेंगे।

पेज 1 का शेष

के कन्ट्रोल में काम करने की संघर्ष समिति और संघर्ष को फैला कर व तीखा करके ही बाटानगर के मजदूर अपने हितों की देख-भाल कर सकेंगे कानपुर की दस कपड़ा मिलों के 35 हजार मजदूरों और उनके परिवारों व सहयोगियों ने फरवरी 89 में पाँच दिन रेलवे लाइन जाम करके कपड़ा मिल मैनेजमेंटों के एक बड़े हमले को विफल कर दिया था—अन्य जगहों के मजदूरों की ही तरह बाटानगर के मजदूरों के लिये भी यह एक अनुकरणीय उदाहरण हैं। अपने हालात के अनुसार पूंजीवादी तन्त्र के किसी नाजुक अंग पर चोट करने के लिये कदम उठाने चाहियें। किसी के चक्कर में पड़ने की बजाय बाटानगर मजदूरों को याद रखना चाहिये कि उनके बिचौलियों का एक सरदार, बंगाल का श्रम मंत्री कहता है कि उसे नहीं मालुम कि समझौता वार्ता क्यों फेल हो गई जबकि हड़ताल के नोटिस के बाद त्रिपक्षी वार्ता श्रम मंत्री की पहलकदमी पर ही आरम्भ हुई थी। बेशर्म श्रम मंत्री अपनी मंडली का एक प्रतिनिधि मात्र हैं .....

असल में बाटा मैनेजमेंट अपनी पालिसी में एक बड़ा परिवर्तन कर रही है। कुछ समय से प्रोडक्शन की बजाय मार्केटिंग की तरफ अत्यधिक झुक रही है मैनेजमेंट का अब पुनः प्रोडक्शन की ओर रूख हैं। यह परिवर्तन सरकार की नई नीतियों की वजह से आया है। नीति में इस उलट-फेर ने बाटानगर में हड़ताल की हालात पैदा की हैं। बाटा फरीदाबाद में भी नीति में परिवर्तन के लक्षण नजर आ रहे हैं।

फरीदाबाद में बाटा फैक्ट्री के मजदूरों को 1988 की घटना नहीं दोहरानी चाहिये। बाटानगर में चार महीने की तालाबन्दी के उस दौर में भी एक दिन व तीन दिन की आल-इन्डिया बाटा हड़तालें की गई थी। लेकिन वह बाटानगर की मजदूरों का फर्जी समर्थन था। फरीदाबाद की बाटा फैक्ट्री में बाटानगर की उस तालाबन्दी के दौरान चार महीने लगातार ओवरटाइम काम के जरिये असल में बाटा मैनेजमेंट का समर्थन किया गया था। ऐसी ही करामात बिचौलिये फिर करके मजदूरों की बरबादी के बीज बोने की कोशिश करेंगे। मजदूरों का हित माँग करता है कि वे चौकस रहें और अपने उन साथियों की राह पर चलें जिन्होंने 1988 बाटानगर तालाबन्दी के दौरान फरीदाबाद बाटा में ओवरटाइम काम करने से इनकार किया था।

फरीदाबाद बाटा मजदूरों के हित में कदम उठाने का यह अच्छा मौका है। और फिर, यहाँ बाटा मैनेजमेंट कम्पनी के स्थाई आदेशों का भी खुला उल्लंघन कर रही हैं। गर्म लोहे पर चोट करना समझदारी का काम माना जाता है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं सम्पादक शेर सिंह के लिए उत्तरांचल प्रिन्टर्स, फरीदाबाद से मुद्रित